

भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5880
गुरुवार, 2 मई, 2013

बी.एच.ई.एल की हितों की रक्षा

5880. श्री सुशील कुमार सिंह:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) की चीन के साथ प्रतिस्पर्धा में इसके हितों और कार्यक्षमता की रक्षा के लिए कदम उठा रही है;
- (ख) यदि हां, तो हाल की अवधि में भेल के धीमे कार्य-निष्पादन तथा घटते हुए क्रयादेशों का क्या कारण है; और
- (ग) भारतीय घरेलू बाजार में 'भेल' के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही चीनी कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा उनकी बाजार में कितनी हिस्सेदारी है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री
(श्री प्रफुल पटेल)

(क): जी, हां ।

(ख): अभी फिलहाल विगत में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कार्य-निष्पादन पर प्रभाव डालने वाले और उसके घटते क्रयादेशों की स्थिति के भी मुख्य कारणों की वजह कारकों के संसर्ग में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :-

- भूमि की अनुपलब्धता, कोयला/ईंधन संयोजन, पर्यावरणीय अनापत्तियों आदि से संबंधित मुद्दों की वजह से घरेलू विद्युत क्षेत्र के बाजार में तैयार हो रहे नए आदेशों में तीव्र कटौती।
- आदेशों का स्थगन अथवा उनको रोक लिया जाना ।
- डिलीवरी का भुगतान करने में ग्राहकों की मजबूरियां और उसकी वजह से कुछ विद्युत परियोजनाओं की कम प्रगति ।
- अति-महत्वपूर्ण बॉयलरों तथा टरबाइन जनरेटरों के लिए देश की निजी क्षेत्र में तैयार हुई नई कंपनियों/संयुक्त उद्यमों की ओर से अति महत्वाकांक्षी प्रतिस्पर्धा जिससे विक्रय प्रभावित हुआ और मार्जिन पर असर पड़ा ।
- मुद्रास्फीतिगत दबाव और अत्यधिक ब्याज दर जिससे लागत/घरेलू मांग और पूंजीगत लागत पर असर पड़ा।
- राजनीतिक खलबली/सीरिया जैसे देशों में सशस्त्र संघर्ष।

(ग): कई सारी चीनी कंपनियां जैसे डोंगफांग, हार्विन पावर, शंघाई इलेक्ट्रिक, सेपको आदि भारतीय बाजार में भेल के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संवर्धित 54,964 मेगावाट की यूटिलिटी पावर जेनरेटिंग क्षमता में से तकरीबन 18,500 मेगावाट (अर्थात 34%) के उपस्कर चीनी आपूर्तिकर्ताओं/विनिर्माणकर्ताओं के हैं ।
